

ਪਹਲਾ ਕੌਲਮ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੀ ਤੀਜਾਰੀ ਲਾਹੌ

आइएनएस रणवीर पर हुए ब्लास्ट मामले में एडीआर नेवी करेगी मामले की जांच

નેડ દલા
આર્થિક

आईएनएस रणवीर पर हुए ब्लास्ट में 3 जवानों को मात्र आर-11 घायल होने के मामले में मुंबई की कुलाबा पुलिस ने एडीआर दर्ज किया है। हालांकि मुम्बई पुलिस के मुताबिक, इस मामले की जांच नेवी ही करेगी। नेवी ने पहले ही बोर्ड ऑफ इंकारायरी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आईएनएस रणवीर के एक आंतरिक कंपार्टमेंट में मंगलवार को विस्फोट हो गया था। इस धमाके में तीन नौ सैनिकों की जान चली गई। वहीं, 11 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद जहाज के चालक दल ने स्थिति को काबू में किया। घायलों को नौसेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल जवानों को कोलाबा नेवी नगर के अधिनी भेजा गया है। आईएनएस रणवीर भारतीय नौसेना का पोर्ट है। आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंकारायरी के आदेश दे दिए गए हैं। आईएनएस रणवीर में ये किस कारण से धमाका हुआ इसे लेकर नौसेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। धमाके की जांच के लिए भारतीय नौसेना ने कमिटी बैठा दी है, जो इस बात की जांच करेगी कि ये धमाका कैसे हुआ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਅਮੰਦਿਆਨ ਚਲਾਕਏ 15

आइडी बरामद हुए

सरायकेला ।

आतकियों की दिल्ली के गाजीपुर मंडी को दहलाने की कशिश नाकाम हो गई। कुछ इसी प्रकार की तैयारी नक्सलियों की झारखंड में भी थी, लेकिन पुलिस ने नाकाम कर दिया। दरअसल माओवादियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरायकेला के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि भाकपा माओवादी जिले के कुचाई इलाके में जगह जगह पर आईडी लगा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लेकर सीआरपीएफ 157 बटालियन के साथ छोपेमारी टीम का गठन किया। जिसमें बीड़ीड़ीएस टीम के पदाधिकारी के साथ कई जवान भी शामिल हुए। सर्च अभियान के दौरान काडेरांगो पहाड़ी के तरफ जैसे ही जवान आगे बढ़े, तब करीब ढेर किमी की दूर पश्चिम दिशा में 15 आईडी बरामद हुए। जो कि जंगल के रास्ते में लगे थे। मौके पर ही बीड़ीड़ीएस टीम के द्वारा आईडी को नष्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादियों का संगठन 26 जनवरी से पहले जिले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। बता दें कि दास्ता रांची, खूंटी, सरायकेला व चाईबासा जिले में पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के फिराक में है। इसकारण पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व सरायकेला के पतराडी हड़ोडारदा जंगल से भी भारी मात्रा में आईडी बम बरामद हुआ था।

ਪਟਨਕਾਟ-ਜਮ੍ਮੁ ਰਾ਷ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਹਿ ਪਰ
ਸੁਰਖਾ ਬਲ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਪਰ

जम्मू । गणतंत्र दिवस समाराह स पहल आतकवादिया के मंसुबों को नाकाम करने और सदिग्द गतिविधि पर नजर रखने के लिए पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर दी है। अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को हिमाचल प्रदेश-पंजाब जांच चौकी पर तैनात किया है। अधिकारियों ने कहा कि राजमार्ग के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर राष्ट्र विरोधी तालों के किसी भी सञ्जिश को नाकाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख सीमावर्ती जिले कठुआ एवं साबा में भी राजमार्ग के पास स्थित सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पूरे इलाके में आतंकवाद रोधी और घुसपैठरों सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जांच चौकियों पर सुरक्षाकर्मियों की तादाद बढ़ाकर उन्हें सरक्त रहने को कहा गया है। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन सहित जम्मू में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ, जो जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) की रक्षा करता है, कड़ी नियरानी बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत पठानकोट में हिमाचल प्रदेश-पठानकोट चौकी पर बीएसएफ को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों से पठानकोट में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है और

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के निलंबित 12 विधायकों के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

२८५

के दौरान न्यायमूल एवं खानावलकर, न्यायमूल दिनेश महेश्वरी और न्यायमूल सीटी रविकुमार की पौत्री ने महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुन्दरम से कहा कि निर्णय का कोई उद्देश्य होना चाहिए। एक प्रबल कारण होना चाहिए, जिससे वित्त उप (सदस्य) अगले सत्र में भी भाग लेने के अनुमति न दी जाए। मूल मद्दा तर्कसंगत निर्णय वे सिद्धांत का है। सुनवाई के दौरान सुन्दरम ने अदालत के समक्ष राज्य विधानसभा के भीतर कामकाज पर्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे के मुद्दे पर दलील दी थी। उन्होंने कहा कि सदन में जो हो रहा है, उसके पर्यायिक समीक्षा घोर अवैधता के मामले में ही होगी अन्यथा इससे सत्ता के पृथक्करण के मूल तत्व पर हमला होगा। सुन्दरम ने कहा कि अगर मरे पास दंड देने की शक्ति है, तब संविधान, कोई भी संसदीय कानून परिभाषित नहीं करता है कि सजा क्या हो सकती है।

श्रीलंका खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए सोना बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। श्रीलंकाई सरकार सोना बेचकर अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने खत्म होते विदेशी मुद्रा के भंडार को देखकर अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉ. डब्ल्यू.ए. विजेवर्धन ने हाल ही में ट्रीटी भी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का गोल्ड रिजर्व कम हुआ है। उन्होंने ट्रीटी में लिखा कि सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व 38.2 करोड़ डॉलर से घटकर 17.5 करोड़ डॉलर का हो गया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर निवार्ड के बाल ने कहा है कि

को बढ़ाने के लिए बेचा है। चीन से करेंसी स्वैप (डॉलर के बजाय एक-दूसरे की मुद्रा में व्यापार करना) के बाद साल के अंत में ही श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया थारिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान है कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने का भंडार था जिसमें से लगभग 3.6 टन सोना बेचा गया है, जिससे उसके पास लगभग 3.0 से 3.1 टन सोना ही शेष है। 2020 में भी केंद्रीय बैंक ने सोना बेचा था। साल की शुरुआत में श्रीलंका के पास 19.6 टन सोने का भंडार था जिसमें से 12.3 टन सोना बेचा गया। श्रीलंका ने साल 2015, 2018 और 2019 में भी सोना बेचा था। गवर्नर कैब्राल ने कहा कि सोने की

कहा, %जब विदेशी भंडार कम होता है, तब हम सोने की होलिंग को कम करते हैं। जब विदेशी भंडार बढ़ रहा था, तब हमारे द्वारा सोना खरीदा गया। एक बार जब रिजर्व स्टर 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ जाएगा, तब केंद्रीय बैंक सोने की होलिंग बढ़ाने पर विचार करेगा। उन्होंने श्रीलंका की स्थिति की तुलना 1991 के भारत से की है जब भारत ने खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए सोना गिरवी रखा था। उन्होंने कहा, %सोना एक रिजर्व है जिसे किसी देश को डिफॉल्ट के कागर पर होने पर अतिम उपाय के रूप में उपयोग करना होता है। इसकारण जब कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध न हो तो सोने की बिक्री संयम से

A collection of gold bars and coins from various countries, including Germany, France, and the United States.

की जानी चाहिए। भारत ने भी 1991 में अपना सोना गिरवी रखा था। उद्घोने कहा, भारत की सरकार ने देश से छुपाया, लेकिन कहानी बाहर आई और सरकार की छवि खराब हुई लेकिन तकालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बाद में लोकसभा में स्वीकार किया कि देश के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब श्रीलंका द्वारा आज सोने की बिक्री का मतलब है कि देश की स्थिति 1991 के भारत जैसी ही है।

भारत में विविध रूपी राजनीति का सदैव स्वागत होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाकर बहुतों को चर्चा का विषय दे दिया है। राजनीति का पहला लक्ष्य ही यही है कि उसके द्वारा स्थापित नेता या नेतागीरी की अधिक से अधिक चर्चा हो। इसमें कोई शक नहीं कि भगवंत मान पंजाब में आप के लिए एक ऐसा चेहरा है, जिनकी पहचान देश-दुनिया में आम आदमी पार्टी से भी पुरानी है। तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की पहले घोषणा करके आम आदमी पार्टी ने एक तरह से बाजी मार ली है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस में हम देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा का खतरा पार्टी उठाने की स्थिति में अभी नहीं दिखती। ऐसे में, भगवंत मान को आगे करके आम आदमी पार्टी ने राज्य के मतदाताओं को सोचने का एक मौका दे दिया है। भाजपा ने भी अभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम स्पष्ट नहीं किया है। जाहिर है, आम आदमी पार्टी अब कह सकती है कि उसके पास चेहरा है और उस चेहरे को उसने आगे कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवंत मान का चयन आसान रहा हो। उनके नाम का विरोध भी हो रहा था। इसके लिए बाकायदा सर्वेक्षण कराया गया है, जिसमें 93 प्रतिशत लोगों ने भगवंत मान को आप का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उम्मीदवार के चयन के लिए सर्वेक्षण की सराहना करनी चाहिए। हालांकि, आप के विरोधी यह कहेंगे कि आप ने सर्वेक्षण का दिखावा किया है और उसके पास भगवंत मान से शक्त कोई नाम पंजाब में नहीं था, लेकिन तब भी पार्टी द्वारा ऐसे किसी सर्वेक्षण की घोषणा मायने रखती है। विवाद की स्थिति में पार्टियों को ऐसे सर्वेक्षण का सहारा लेने में हिचकना नहीं चाहिए। चयन में हाईकमान की मर्जी से बहुत श्रेष्ठ है सार्वजनिक सर्वेक्षण। वास्तव में, अगर पार्टियों के अंदर संगठन के चुनाव होते, तो हाईकमान की मर्जी या ऐसे सर्वेक्षणों की नीबत ही नहीं आती, लेकिन हमारे यहां राजनीति में जो सामंती व्यवस्था है, उसमें संगठन चुनाव के पक्षधर कितने होंगे, कहना मुश्किल है। यह अच्छी बात है कि

मान राजनात म नए नहा ह। साल 2011 स हा वह राजनीति में कमोबेश सक्रिय है। साल 2014 और 2019 में संगरुर से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके राजनीतिक वजन को नकारा नहीं जा सकता। 48 साल के भगवंत मान ऐसी हस्ती हैं, जिनकी छवि विदृशक की है, लेकिन उनमें पर्याप्त गंभीरता भी रही है और उनके क्षेत्र में लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। राजनीति में आने के बाद वह कॉमेडी से दूर हैं। वैसे तो वह साल 1992 से ही कॉमेडी कर रहे हैं, पर उन्हें देशव्यापी ख्याति ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज से 2008 में मिली थी। पंजाबी कॉमेडियन से वह भारतीय कॉमेडियन में तब्दील हुए थे। यह देश किसी कॉमेडियन को ऊंचे पढ़ों पर देखने का आदि नहीं है। तमिलनाडु को अगर छोड़ दें, तो बाकी भारत में बड़े अभिनेताओं को भी लोग नेता के रूप में आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में, मुख्यमंत्री पद के लिए भगवंत मान की उम्मीदवारी एक कामयाबी है। चुनावी मैदान में उन्हें पूरे दमखम और मजबूत चरित्र के साथ सामने आना होगा। राजनीति कर्तव्य कॉमेडी नहीं है, यह बात पंजाब में दूसरी पार्टियां अब बहेतर समझ रही होंगी।



मन को बांधना

जग्गी वासुदेव

अगर आप मन के परे चले जाएं तो आप पूरी तरह से कर्मिक बंधनों के भी परे चले जायेंगे। आप को कर्मों को सुलझाने में असाल में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, व्यायोकि जब आप अपने कर्मों के साथ खेल रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह मन का एक जाल है। बीते हुए समय का कोई अस्तित्व नहीं है पर आप इस अस्तित्वहीन आयाम के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, जैसे कि वही वास्तविकता हो। सारा भ्रम बस यही है। मन ही इसका आधार है। अगर आप मन से परे चले जाते हैं तो एक ही झटके में हर चीज़ के पार चले जाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के सभी प्रयास बस इसीलिए हैं कि मन से परे कैसे जाएं? मन की सीमाओं से बाहर जा कर जीवन को कैसे देखें? बहुत से लोगों ने योग को अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया है। लोग कहते हैं-'अगर आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, तो ये योग है। खुद से परे चले जाते हैं तो योग है। भौतिकता के नियमों से प्रभावित नहीं हैं तो योग है।' ये सब बातें ठीक हैं। अद्भुत परिभाषाएं हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है, मगर अपने अनुभव की दृष्टि से आप इनसे संबंध नहीं बना पाते। किसी ने कहा,'अगर आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो आप योग में हैं।' आप नहीं जानते कि ईश्वर कहाँ हैं तो आप एक कैसे हो सकते हैं? पर पतंजलि ने ऐसा कहा-'मन के सभी बदलावों से ऊपर उठना, जब आप मन को समाप्त कर देते हैं, जब आप अपने मन का एक भाग बना बंद कर देते हैं, तो ये योग है।' इस दुनिया के सभी प्रभाव आप में सिर्फ़ मन के माध्यम से ही आ रहे हैं। अगर आप, अपनी पूर्ण जगरूकता में, अपने मन के प्रभावों से ऊपर उठते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज़ के साथ एक हो जाते हैं। आपका और मेरा अलग-अलग होना, समय-स्थान की सारी भित्ताएं भी, सिर्फ़ मन के कारण होती हैं। ये मन का बंधन है। अगर आप मन से परे हो जाते हैं तो समय-स्थान से भी परे हो जाएंगे। अगर आप मन के सभी बदलावों और अभिव्यक्तियों से ऊपर उठते हैं तो आप मन के साथ खेल सकते हैं। अपने मन का उपयोग जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं पर अगर आप मन के अंदर हैं तो आप कभी भी मन की प्रकृति को नहीं समझ पायेंगे।

ਕੁਂਤਿ ਸਮਾਂ

ਮੂਲ ਕਰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਸੇ ਛਿਪਾਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। - ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

बाजार की बड़ी कंपनियों से बचाएं किसान को

देविंदर शर्मा

भारतीय नीति-निर्माताओं ने अमेरिकी कृषि नीतियों के अनुरूप बनी बाजार व्यवस्था की असफलता और यहाँ तक कि तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने से भी सीख नहीं ली है कीमतों का निर्धारण 'मांग-आपूर्ति संतुलन वाले सिद्धांत' से होता है, यही दोहरा रहे हैं। जबकि अनुभव बताता है कि उपरोक्त बाजार व्यवस्था में, उत्पाद के भाव में उत्तर-चढ़ाव अमेरिकी किसानों की सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने में असफल रहा है, अब बारी पशुपालकों की है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भैंस इस विद्रूपता को स्वीकार किया है जब उन्होंने कहा, 'पचास साल पहले खुदरा दुकान से बीफ खरीदने में चुकाए गए प्रत्येक डॉलर से पशुपालक के हिस्से 60 सेंट आते थे। आज वह घटकर 39 सेंट रह गया है। ऐसे ही उस वक्त सूअर-पालक को उपभोक्ता वैद्यर डॉलर से 48-50 सेंट पहुंचते थे, जो फिलहाल लगभग 19 सेंट है। दूसरी ओर बड़ी कंपनियां भारी मुनाफा बना रही हैं। जबकि अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि आने वाले साल में बीफ की खुदरा कीमत में 21 प्रतिशत, सूअर-गोश्त में 17 फीसदी तो मुर्गे के मीट में 8 प्रतिशत औसतन मूल्य वृद्धि होती रहेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने आगे कहा, 'कंपनियों का मुनाफा बढ़ने के साथ-साथ अंतिम विक्रय बिंदु पर उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती गई, किंतु मटी में किसान को मिलने वाला मूल्य घटत चला गया।' इसको आगे विस्तार देते हुए अमेरिकी कृषि विभाग के सचिव टॉम विल्सेक ने अपने ट्रीटमेंट में कहा 'इन गर्भमयों में मर्म भेट आयोवा प्रांत के किसानों से हुई, जिन्हें मांस प्रसंस्करण इकाइयों को बेचे अपने प्रत्येक पशु पर 150 डॉलर का घाट उठाना पड़ा, जबकि उसी उद्योग ने एक जानवर का मांस बेचकर 1800 डॉलर का मुनाफा बनाया। कल्पना करें कि मांस प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां किसान की आमदनी मारक कर देंगी किस मात्रा में लाभ कमा रही हैं।' भारत में, हम अक्सर आदित्य और व्यापारियों पर बतौर बिचौलिए मुनाफाखोरी का इल्जाम लगाते आए हैं, लेकिन अमेरिका के मांस उद्योग के 85 प्रतिशत हिस्से पर काबिज चार बड़ी कंपनियां असल में इनसे कहीं ज्यादा बड़े बिचौलिए हैं, जिनकी प्रवृत्ति बड़ी शार्क मछली सरीखी है भारत में भी, बड़ी कंपनियां, जो उक्त शार्कों से कम नहीं, उनके

आमद मंडी व्यवस्था में सही ठहराने की खातिर आदतियों के निशाने पर लिया जा रहा है। यह ठीक है कि बिचौलियों पर नियंत्रण-अंकुश बनाने की आवश्यकता है लेकिन अमेरिकी अनुभव बताता है कि मांस उद्योग को सुदृढ़ करने की सोच से अपनाए उपाय वास्तव में जहां मंडी का नियंत्रण चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में होने का जरिया बने, वहीं पशुपालक किसान कई आजीविका दूधर करते गए। पिछले सालों के दौरान, मांस कई खुदरा कीमतों में सिलसिलेवार कमी आने से पशुपालक किसानों की पीढ़ियां इस व्यवसाय से किनारा करती गईं। जैसे-जैसे यह ग्रामीण तबका लुप्त होता गया वैसे-वैसे 'खेत से प्लेट' वाले प्रयोग केवल उद्योग आधारित कृषि को ही बढ़ावा देने में सहायक होता गया। अमेरिकी कृषि नीति की यह असफलता 'मुक्त मर्ड व्यवस्था' से किसानों की बाबौदी का मुंह बोलता उदाहरण है। तुरंत यह कि इस तथ्य को अभी भी नकारा जा रहा है कि बहुचर्चित 'मांग-आपूर्ति सिद्धांत' पशुपालक किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने में असफल रहा है। यही कुछ पहले डेरी उद्योग के साथ हो चुका है। खेत से लेकर खुदरा बाजार तक सप्लाई चेन को इसी तरह 'सुदृढ़' किया जा रहा है। वास्तव में, केंद्रीकरण होने से एकाधिकार बनता है और चंद कंपनियों का गुट, उत्पादक एवं उपभोक्ता, दोनों का बेदी से दोहन करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपना हिस्सा हड्डपते देख अमेरिकी राष्ट्रीय किसान यूनियन न अब 'किसानों को न्याय' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए हुए हैं ताकि कॉर्पोरेट कंपनियों का एकाधिकार खत्म कर एंटी-द्रेस कानून का पालन बेहतर कड़ाई से हो सके। अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया में, राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद बड़े खिलाड़ियों द्वारा वस्तु-कीमत ऊंची बनाए रखने वाले खेल पर नकेल कसने का आद्वाना किया है। इसकी शुरुआत सरकार ने छोटी मांस प्रसंस्करण इकाइयों को 1 विलियन डॉलर मुहैया करवाकर की है ताकि स्थानीय इकाइयां महाकाय कंपनियों को टकर दे सकें। बेशक यह उपाय सर्वोत्तम नहीं है, किंतु कम-से-कम यह स्वीकारोक्ति जरूर है कि कॉर्पोरेट एकाधिकार आपूर्ति के दोनों ओर -उत्पादक और उपभोक्ता- का किस कदर दोहन कर रहा है। हालांकि बेहतर हल है, कृषि उत्पाद और पशुधन को न्यूनतम मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करना। आय समानता बनाने की मांग को लेकर वर्ष 1979 में राजधानी वाशिंगटन में किसानों का विशाल ट्रैवर्टर

विरोध इसीलिए था। भारतीय किसान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि मड़ी में कोई भी खरीद इस कीमत से कम पर न होने पाए। इसी तरह यूरोप में भी किसान अपने लगातार जारी संकट से निजात पाने को गारंटिड न्यूनतम उचित मूल्य की मांग बार-बार करते आए हैं। पिछले कुछ सालों से खेती से लगातार घटती आय की वजह से ही वैश्विक कृषि संकट बना है। इसका उदाहरण वर्ष 2005 है, जब कनाडा की राष्ट्रीय किसान यूनियन ने 'कृषि संकट - कारण एवं निदान' नामक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इसमें विगत 20 साल (1985-2005) के दौरान दुनियाभर में व्याप्त अभूतपूर्व खेती संकट के पीछे कारण गिनाए थे। यह टीक वही थे जिन्हें यूएनसीसीएडी ने भी अपने अध्ययन में स्वीकार किया था कि विश्वभर में उत्पाद की कीमत, मुद्रास्फीति जोड़ने के बाद, पिछले 20 सालों से जस-की-तस रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यूरोप में अपनाई गई उच्च नियंत्रणों वाली कृषि-आर्थिक नीतियों और ऑस्ट्रोलिया, अर्जांटाइना की अपेक्षाकृत कम नियंत्रण वाली, किंतु इतनी ही मारक नीतियों ने कृषि-संकट को गहराया ही है। कनाडा की राष्ट्रीय कृषि यूनियन को यह भी रोध था कि 2005 में मिलने वाली कीमतें 1930 के दशक में आई महामंदी के वक्त रहे मूल्यों से कहीं कम हैं। वह भी ऐसे समय पर जब विश्वभर की आर्थिकी, स्टॉक मार्केट, व्यापार में विस्मयकारी उछल दुआ हो और खाद्यान्न उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ हो। इसमें कृषि-संकट का हल निकालने को 16 सूत्रीय पैकेज में उपाय सुझाए गए थे, सूची में न्यूनतम कृषि आय सुनिश्चित करना सबसे ऊपर था। यूनियन ने सरकार को कृषि आय-सहायता कार्यक्रम लागू करने को कहा ताकि कम-से-कम 95 प्रतिशत किसान उत्पादन की लागत निकाल पाएं, इसकी गणना में श्रम, ग्रंथांश का मेहनताना और निवेश पर सूद भी शामिल हो। लेकिन अमेरिका की तरह कनाडा की सरकार ने भी गारंटिड मूल्य बनाने की किसानों की इस जायज मांग को नज़रअंदाज़ कर दिया। यह होना ही था क्योंकि वर्षोंकि दुनियाभर की सरकारें कृषि-पैकेजों-पशुपालकों की सम्माननीय आजीविका सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करने से कतराती हैं। नीतीजतन, विश्वभर के किसान घाटा उठाकर भी अनाज उगाने का अभिशाप ढो रहे हैं।

इमरान साहब, बेहतर होगा आप हमारी छोड़ अपने देशवासियों की चिंता करें

(लेखक- तनवीर जाफ़री)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों ट्यूटर के माध्यम से यह चिंता ज़ाहिर की कि-'भारत में अल्पसंख्यकों को अतिवादी समूह निशाना बना रहे हैं और इस तरह का एजेंडा क्षेत्रीय शांति के लिए एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है। उन्होंने यह आरोप दिसंबर में हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद के दौरान कुछ कथित संतों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक व भड़काऊ भाषण दिए जाने के सन्दर्भ में लगाये। इमरान खान ने यह भी पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में अल्पसंख्यकों के सामूहिक संहार की मांग का समर्थन करती है, जिस देश में 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं? उन्होंने कहा कि यही समय है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पूर्व भी गत माह पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारत के अधिकारी को पेश होने के लिए कहा था और हरिद्वार की कथित धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों को लेकर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। उस समय भी पाकिस्तान ने भारतीय पक्ष से कहा था कि कथित भड़काऊ भाषणों को नागरिक समाज गंभीर चिंता के साथ देख रहा है। भारतीय मुसलमानों को लेकर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा व्यक्त की जाने वाली 'कथित चिंता' कई तरह के सवालों को जन्म देती है। पहला तो यह कि क्या 'पाकिस्तान जैसे देश' के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर यह हक् पहुँचता है कि वे भारतीय मुसलमानों के प्रति अपनी चिंता जतायें? स्वयं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है यह भी दुनिया से छुपा नहीं है। पाकिस्तान में तो हरिद्वार की धर्म संसद की तरह आये दिन किसी भी वर्ग अथवा विचारों की भीड़ खड़ी होकर किसी भी समुदाय को ललकारने लगती है। उर्वे नेस्तो-नाबूद करने की बात करती रहती है। आये दिन अल्पसंख्यक समाज की किसी लड़की के अपहरण, उसका

जबरन धर्मपरिवर्तन कर विवाह करने जैसी खबरें आती रहती हैं। इसी पाकिस्तान में केवल मंदिरों, गुरुद्वारों व चर्च पर ही नहीं बल्कि मुसलमानों के ही अलग अलग वर्ग से जुड़ी मस्जिदों, दरगाहों, इमाम बारगाहों तथा जुलूस आदि जैसे धार्मिक आयोजनों पर न केवल साधारण हमले बल्कि आत्मघाती हमले तक किये जाते हैं। पाकिस्तान ही वह देश है जिसने तालिबान को गोद लिया उसकी परवरिश की और अब वही तालिबान पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चला है? पाकिस्तान की भारतीय मुसलमानों के प्रति चिंता यह सवाल भी खड़ा करती है कि आपके देश के लोगों, आपकी सरकार व नेतृत्व ने जो कि 'मुस्लिम परस्त' होने का दावा किया करता था उसने पूर्ण पाकिस्तान के अपने ही 'कौमी भाईयो' (मुसलमानों) के साथ ऐसे बरताव कर्यों किये कि 1971 जैसे हालात बने? उस वक़्त कहाँ चला गया था पाकिस्तान का मुस्लिम प्रेम? सही मायने में तो धर्म के नाम पर किया गया वह सबसे बड़ा धोखा था कि भारतीय मुसलमानों को धर्म नाम पर वरणलाया गया और 1947 व 1971 के बीच ही क्षेत्रवाद ने अपना झंडा धर्म से भी ऊँचा कर लिया? आज रोहगिया मुसलमानों पर बुरा वक़्त आया है। पाकिस्तान की रोहगिया मुसलमानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाई या सुनाई देती। जबकि बांग्लादेश उनको शरण देने वाला एक प्रमुख देश है। पिछले दिनों पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुये इमरान खान ने स्वयं स्वीकार किया कि 'पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार को इन्हें बड़े राजस्व घटे और चालू खाता घटे का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हमारे मित्र देश चीन, यू.ए.ई व सऊदी अरब ने फ़ंड ना दिया होता तो हम डिफॉल्ट कर गए होते। हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। रुपए को गिरने से बचाने के लिए डॉलर नहीं थे'। इमरान खान द्वारा दिया गया यह वक्तव्य जहां पाकिस्तान की ढूबती अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है वहीं यह सोचने के लिये भी मजबूर करता है कि भारत में मस्लिम विरोधी आयोजन की चिंता करने वाले इमरान खान ने

आखिर चीन के जिंजियांग प्रांत के उईगर मुसलमानों के साथ चीन सरकार द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध कभी चीनी दूतावास के अधिकारी को बुलाकर अपने 'धर्म-प्रेम' का इज़हार कर्यों नहीं किया ? चीन में तो मुसलमानों के लिये कई बड़े हिरासत केंद्र केंद्र बनाये गये हैं जहां उनके साथ वह सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परन्तु दुनिया तो खामोश है ही, आश्वर्य है कि दुनिया के मुसलमानों की वित्ती करने वाला पाकिस्तान भी खामोश है ? क्या इस खामोशी की वजह यही है कि चीन ने फ़ंड देकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है ? दरअसल दोनों देश कभी एक ही थे इसलिये दोनों ही देशों की तर्ज़-ए-सियासत भी एक जैसी ही है। दोनों ही देशों की सरकारों को जब जनता का ध्यान जनसरोकार से जुड़े मुद्दों से भटकाना होता है उस समय दोनों ही देश एक दूसरे पर 'अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव व जुल्म' का मुद्दा उठालने लगते हैं। कश्मीर को भी केंद्र में रखकर दोनों ही देश अपने अपने देशवासियों के बीच 'राष्ट्रवाद' की ज्योत जलाने लगते हैं। मँहार्गाई व बेरोज़गारी दोनों ही देशों की सरकारों के संभाले नहीं संभल रहे हैं परन्तु एक दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की वित्ती सभी को सताये रहती है। अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने व उन्हें न्याय दिलाने के बजाये 'स्वर्घर्मी' होने के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाये जाते हैं। भारतीय मुसलमान आज भी जितना खुश व सुरक्षित भारत में है उतना दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं। भारतीय मुसलमानों के साथ देश के गांधीवादी विचारधारा के उदारवादी हिन्दू हमेशा से खड़े हैं। आज भी भारत में जो सरकार खांटी हिन्दुवाद का झण्डा उठाये है जिसके संरक्षण के चलते हरिद्वार की कथित धर्म संसद जैसी धर्म विशेष का विरोध करने वाली ब्यानबाजियाँ हो रही हैं, उसका सबसे अधिक विरोध भारतीय हिन्दू समाज से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाइयां हो रही हैं। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी निदा की जा रही है।

	1	5	6		2			7
7	2			8				3
3		8	5	9			4	
	9		7		4	2	6	8
			1		3			
5	7	6	8		9		1	
	5			4	8	7		6
9				7			2	1
6			2		5	4	8	

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो दूसरा लिपेण्ड ध्यान रखें।

बायें से दायें:-

1. डिगो मारिया, इरकान खान, बिपाशा बसु, प्रीति झंगियांनी की फिल्म-3
 3. 'रोहिता रे, तेरे रंग में, रंगा है मेरा मन' गीत वाली फिल्म-2,3
 6. फिल्म 'धर का चिराग' में नायिका-3
 8. 'तीव्रा तीव्रा इश्क ना करियो' गीत वाली फिल्म-2
 10. 'चिद्धी आई है वनत से' गीत वाली संजयदत्त, पूम्प छिल्ली की फिल्म-2
 12. सनी देओल, सुमित्रा सेन की 'मैं अपना नाम भूला' गीत वाली फिल्म-2
 13. 'उड़ो रख ने बनाया है कमाल' गीत वाली अभिनव खान फिल्म-2
 14. 'रुकी रुकी की जिंदगी' गीत वाली फिल्म-2
 15. 'सुबह सुबह जब खिड़की खोले' गीत वाली बिहारी अनंद, कृतिका पाने, सोनू नायिया की फिल्म-2
 17. मिथुन चक्रवर्ती की 'बाबूल का ये घर बहना' गीत वाली फिल्म-2
 18. 'आके भर तो बाजुओं में गीत वाली सलमान खान, स्नेहा उल्लाल की फिल्म-2
 19. दिलापीकुमार, की 'वनत राह में वनत के जीवा' गीत वाली फिल्म-3
 21. 'आई है तेरे आने की चिढ़ी' गीत वाली राकेश रोशन, राज बब्बर, अमोग पालकर, रेखा की फिल्म-2
 22. देव अनंद, निम्मी की 'उस रूपनगर के सौदागर' गीत वाली फिल्म-2
 24. 'नशा है आज देख तो' र वाली सनी देओल, विवेक औबेराय, समीरा रेड़ी की फिल्म-2
 25. फिल्म 'ताजमहल' की नायिका-2
 28. जीरंदू, रीनाराय, रामेशवर्ण की फिल्म-2
 29. सुनीलदत्त, नूतन की 'मेरे गाथा गाथों का लीडर' गीत वाली फिल्म-5
 30. 'ये मूलतात एक बहाना है' गीत वाली जीरंदू, सुलश्मा पंडित की फिल्म-4

फिल्म वर्ग पहेली-2025

A crossword puzzle grid with numbered squares from 1 to 31. The grid has dark gray shaded cells at various intersections. The numbered squares are:

- Row 1: 1, 2, 3, 4, 5
- Row 2: 6, 7, 8, 9
- Row 3: 10, 11, 12, 13
- Row 4: 14, 15, 16
- Row 5: 17, 18, 19, 20
- Row 6: 21, 22, 23
- Row 7: 24, 25, 26
- Row 8: 27, 28, 30, 31
- Row 9: 31

- | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|------|----|-----|
| कै | मि | ली | ची | ता | दे | वा | र |
| ला | ला | रु | ख | म | स्ती | जा | |
| पा | प | दा | | आ | न | बा | जी |
| ग | | शा | ली | मा | र | गु | रु |
| ल | गा | न | | जू | ली | द | स |
| प | | दा | स्ता | न | ड | र | त्व |
| न | ज | र | | म | डं | र | ग |
| ह | | खा | की | | अं | जा | म |
| नू | री | | | न | सी | ब | जा |
| ले | कि | न | | मा | म | नी | ष |



आईसीआईसीआई सिवयोरिटीज का मुनाफा 42 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली । आईसीआईसीआई सिवयोरिटीज का मुनाफा चालू, वित्त वर्ष की दिसंबर में समाप्त तिमाही में 42 प्रतिशत बढ़कर 30 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आईसीआईसीआई सिवयोरिटीज ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में बताया कि उसे इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 257 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी की आय 31 दिसंबर को समाप्त चालू, वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 52 प्रतिशत बढ़कर 942 करोड़ रुपए पर पहुंच गयी। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में वह 620 करोड़ रुपए थी। कंपनी की हर क्षेत्र में मजबूत कारोबार से आय बढ़ी है। आईसीआईसी सिवयोरिटीज के पास वर्तमान में 70 लाख ग्राहक हैं। इसमें 6.8 लाख ग्राहक कंपनी ने समीक्षालीन तिमाही में जोड़े हैं।

पावर फाइनेंस, आईसी ने ऋण पर व्याज दरों में 0.4 प्रतिशत की कटौती की

मुंबई । सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और आईसी लिमिटेड ने अपने सभी प्रकार के ऋण पर व्याज दरों में 0.4 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। बिजली मंत्रालय ने कहा कि एपीएसी और आईसी ने अपने हर तरह के ऋण पर व्याज दरों को 0.4 प्रतिशत तक बढ़ाया है। मंत्रालय ने कहा कि कंजी की कम लागत के कारण इन संगठनों ने व्याज दरों को कम किया है। एपीएसी और आईसी पहले से ही 6.25 प्रतिशत की न्यूनतम व्याज दरों पर अल्कालिक ऋण प्रदान कर रही हैं। बिजली के अनुसार, केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं प्रतिक्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दरों को कम करने और प्रतिस्पद्य बढ़ाने के लिए दोनों कंपनियों द्वारा जारी प्रवासों पर सतोष व्यक्त किया। उहोंने कहा कि ऋण की दरों में लागतार कमी करने से बिजली इकाइयों को प्रतिस्पद्य दरों पर उत्तर लेने तथा बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी।

क्रेडिटर पुराने दो पहिया वाहनों का कारोबार बढ़ाएगी

नई दिल्ली । पुराने दो पहिया वाहनों के खरीद-बिक्री मंच क्रेडिटर ने बुधवार को कहा कि अपना कारोबार बढ़ाने पर विचार कर रही है। क्रेडिटर ने कहा कि वह कारोबार का विस्तार करने के लिए 2022-23 में करीब 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 110 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। उसकी योजना वित्त वर्ष 2022-23 में 30 से अधिक शोरूम खोलने की है। कंपनी की योजनाओं के बारे क्रेडिटर के एक वे रिपोर्ट अधिकारी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान हमारे कारोबार में असाधारण तरीके से तेजी आई। कोविड के बाद का प्रतिसाद बहुत बढ़िया था इसलिए हमने अपनी विस्तार योजनाओं को अमलीयता का फैसला किया। कंपनी ने अनुदानादार, राजकोट, वडोदरा, गुजरात और फरीदाबाद में अपने परिचालन का विस्तार किया है। जबकि बैंगलुरु, पुणे, जयपुर, भैलवाड़ा, चिंतौड़ा और दिल्ली में उसकी मौजूदगी पहले से थी।

बजाज फाइनेंस का मुनाफा 2,125 करोड़ रुपये

नई दिल्ली । बजाज फाइनेंस का चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में मुनाफा 85.5 प्रतिशत बढ़कर 2,125.29 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समाप्त तिमाही में 1,145.98 करोड़ रुपए का मुनाफा यात्रा था। शेयर बाजारों के भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 8,535.06 करोड़ रुपए पर पहुंच गई जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समाप्त तिमाही में 6,658.34 करोड़ रुपए थी। तीसरी तिमाही में कंपनी की प्रबंधन-अधीक्षी कुल परिसंपत्तियां 26 प्रतिशत बढ़कर 1,81,250 करोड़ रुपए पर पहुंच गईं, जो एक साल पहले समाप्त तिमाही में 1,43,550 करोड़ रुपए थीं। तिमाही के दौरान कंपनी की व्याज आय 40 प्रतिशत बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समाप्त तिमाही में 4,296 करोड़ रुपए थी।

श्रेई समूह के समाधान पेशेवर के तौर पर ईवाई अधिकारी की नियुक्ति हितों का टकराव: एफसीआरपी

मुंबई: एफसीआरपी ने भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अधिकारी ब्रैड (आईसीआई) के कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे श्रेई समूह के लिए समाधान पेशेवर के तौर पर सलाहकार फर्म ईवाई के एक शोध अधिकारी की नियुक्ति पर चिंता जारी हुए कहा है कि वह हितों के टकराव से जुड़ा मामला है। कारोबारियों के दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े समूह एफसीआरपी ने संसद के प्रसुध नवरंग सैनी और कंपनी मामलों के सचिव राजेश वर्मा को भी भेजे थे। इस पत्र में कहा जाता है कि ईवाई वित्तीय एवं पुनार्गठन सलाहकार के तौर पर श्रेई समूह के साथ काम कर रही थी। ऐसे में ईवाई के ही एक शोध अधिकारी को समाधान पेशेवर नियुक्त करना अचिन्तन ही है। श्रेई समूह पर कई बैंकों की करीब 30,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके चुकामों में नाकाम रहने के बाद भारतीय बैंक ने श्रेई समूह को दिवाला सहित के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहित (आईसीआरपी) के तहत एक शोध अधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट तौर पर दिया गया।

एफसीआरपी एक समाधान प्रक्रिया द्वारा दिया गया।

समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनियों के लिए

मंच (एफसीआरपी) ने कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे श्रेई समूह के लिए समाधान पेशेवर के तौर पर सलाहकार फर्म ईवाई के एक शोध अधिकारी की नियुक्ति पर चिंता जारी हुए कहा है कि ईवाई वित्तीय एवं पुनार्गठन सलाहकार के तौर पर श्रेई समूह के साथ काम कर रही थी। ऐसे में ईवाई के ही एक शोध अधिकारी को समाधान पेशेवर नियुक्त करना अचिन्तन ही है। श्रेई समूह पर कई बैंकों की करीब 30,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके चुकामों में नाकाम रहने के बाद भारतीय बैंक ने श्रेई समूह को दिवाला सहित के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहित (आईसीआरपी) के तहत एक शोध अधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट तौर पर दिया गया।

एफसीआरपी एक समाधान प्रक्रिया द्वारा दिया गया।

समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनियों के लिए

मंच (एफसीआरपी) ने कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे श्रेई समूह के लिए समाधान पेशेवर के तौर पर सलाहकार फर्म ईवाई के एक शोध अधिकारी की नियुक्ति पर चिंता जारी हुए कहा है कि ईवाई वित्तीय एवं पुनार्गठन सलाहकार के तौर पर श्रेई समूह के साथ काम कर रही थी। ऐसे में ईवाई के ही एक शोध अधिकारी को समाधान पेशेवर नियुक्त करना अचिन्तन ही है। श्रेई समूह पर कई बैंकों की करीब 30,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके चुकामों में नाकाम रहने के बाद भारतीय बैंक ने श्रेई समूह को दिवाला सहित के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहित (आईसीआरपी) के तहत एक शोध अधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट तौर पर दिया गया।

एफसीआरपी एक समाधान प्रक्रिया द्वारा दिया गया।

समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनियों के लिए

मंच (एफसीआरपी) ने कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे श्रेई समूह के लिए समाधान पेशेवर के तौर पर सलाहकार फर्म ईवाई के एक शोध अधिकारी की नियुक्ति पर चिंता जारी हुए कहा है कि ईवाई वित्तीय एवं पुनार्गठन सलाहकार के तौर पर श्रेई समूह के साथ काम कर रही थी। ऐसे में ईवाई के ही एक शोध अधिकारी को समाधान पेशेवर नियुक्त करना अचिन्तन ही है। श्रेई समूह पर कई बैंकों की करीब 30,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके चुकामों में नाकाम रहने के बाद भारतीय बैंक ने श्रेई समूह को दिवाला सहित के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहित (आईसीआरपी) के तहत एक शोध अधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट तौर पर दिया गया।

एफसीआरपी एक समाधान प्रक्रिया द्वारा दिया गया।

समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनियों के लिए

मंच (एफसीआरपी) ने कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे श्रेई समूह के लिए समाधान पेशेवर के तौर पर सलाहकार फर्म ईवाई के एक शोध अधिकारी की नियुक्ति पर चिंता जारी हुए कहा है कि ईवाई वित्तीय एवं पुनार्गठन सलाहकार के तौर पर श्रेई समूह के साथ काम कर रही थी। ऐसे में ईवाई के ही एक शोध अधिकारी को समाधान पेशेवर नियुक्त करना अचिन्तन ही है। श्रेई समूह पर कई बैंकों की करीब 30,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके चुकामों में नाकाम रहने के बाद भारतीय बैंक ने श्रेई समूह को दिवाला सहित के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहित (आईसीआरपी) के तहत एक शोध अधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट तौर पर दिया गया।

एफसीआरपी एक समाधान प्रक्रिया द्वारा दिया गया।

समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनियों के लिए

मंच (एफसीआरपी) ने कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे श्रेई समूह के लिए समाधान पेशेवर के तौर पर सल

**भ्रष्टाचार प्रतियोगिता में
भाग लो ईनाम जीतो
&
भ्रष्टाचार की जानकारी देने
पर ईनाम जीतो**

krantisamay@gmail.com



9879141480

fight against corruption india

**भारत में भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई**